



2025:AHC:175502

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 24831 of 2025

Sunrise Packers Through Its Proprietor Syed Wiqar
Ul Haque

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P. and another

.....Opposite
Party(s)

Counsel for Applicant(s) : Rishabh Kesarwani, Shiva Pandey,
Shrish Chandra, Siddhant Sahai
Counsel for Opposite Party(s) : G.A., Lalit Kumar Ojha, Pawan Kumar
Shukla

Court No. - 75

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Shrish Chandra, learned counsel for the applicant as well as Sri S.P. Singh, learned State Law Officer for the State and Sri Pawan Kumar Singh, learned counsel for the O.P. no.2.
2. A joint statement has been made by the leaned counsel for the parties that they do not want to file any affidavit.
3. With the consent of the parties, the case is being decided at the fresh stage.
4. This is an application under Section 528 of BNSS preferred by the applicant for quashing the order dated 01.07.2025, passed by the District/Session Judge Amroha in Appeal No. 81 of 2025 dated 26.06.2025, under Sections 138, 141 Negotiable Instrument Act, Police Station Saidangali, District Amroha Arising out of Case No. 262 of 2024, under Sections 138, 141 Negotiable Instrument Act, Police Station Saidangali, District Amroha, Pending Before the District/Sessions Court, Amroha and to set aside the order passed, under sec 148 of Negotiable Instrument Act 1881, by the said court against the applicant to pay the 20% of the total compensation amount i.e Rs. 7,60,000 mandatorily within 15 days from the date of the order which shall expire on 15.06.2025.
5. The case of the applicant is that post-lodging of the complaint under Section 138 of the N.I. Act, the applicant came to be convicted on

02.06.2025 by the Court of Civil Judge (Jr. Div.)/ FTC-1st/ Judicial Magistrate, Amroha in Complaint Case no.262 of 2024 for imprisonment of one year and fine to the tune of Rs.38,00,000/- against which an appeal bearing number "8 of 2025" came to be preferred by the applicant along with the stay application for staying the conviction, sentence and recovery and on 26.6.2025, the court below proceeded to pass an order directing for deposit of 20% of the interim compensation to the tune of Rs.7,60,000/- out of Rs.38,00,000/-.

6. Questioning the same, the present application has been preferred.

7. Learned counsel for the applicant has submitted that order dated 26.06.2021 cannot be sustained for the simple reason that the same is not as per the mandate of the Hon'ble Apex Court in the case of **Jamboo Bhandari Vs. M.P. State Industrial Corporation Ltd., (2023) 0 SC 8855**. He submits as to whether the case of the applicant falls under the exceptional category or not has not been considered. However, the learned counsel for the applicant as per the instructions received from his clients submits that the applicant shall deposit 10% of the total amount of Rs.38,00,000/-.

8. Learned A.G.A. as well as the counsel for the O.P. No.2 submit that the sword of conviction is hanging on the neck of the applicant, however he could not dispute the fact that there has been no consideration with regard to the fact whether the case of the applicant falls under the exceptional category or not. According to him, in case the applicant seeks to deposit 10% then there is no objection and the matter be remitted back to pass a fresh order.

9. I have heard the submissions so made across the Bar and perused the record carefully.

10. The order dated 26.06.2025 reads as under:-

"**26.06.2025**- आज यह ३ए फौजदारी अपील मय 4 बी शपथ पत्र विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांकित 02.06.2025 के विरुद्ध मुसरिम की आख्या सहित प्राप्त होकर पेश हुई।

आदेश हुआ कि-

प्रस्तुत फौजदारी अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आक्षेपित निर्णय एव दण्डादेश व मुंसरिम रिपोर्ट का अवलोकन किया।

यह फौजदारी अपील, अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी. प्रथम / न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के द्वारा परिवाद संख्या-262/2024, सतेन्द्र कुमार बनाम सनराईज पैकर्स द्वारा प्रोपराईटर वकार उल्ला , अन्तर्गत धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना सैदंगली, जिला अमरोहा में पारित निर्णय एवं

दण्डादेश दिनांकित 02.06.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निर्णय व दण्डादेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त सनराईज पैकर्स द्वारा प्रो० वकार उल्ला को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषी पाते हुए के एक वर्ष के साधारण कारावास व अंकन 38,00,000/- (अड़तीस लाख) रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं अर्थदण्ड अदा करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध दण्डित अपील ग्राह्य है। अतः यह फौजदारी अपील अंगीकृत की जाती है। पंजीकृत हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। अपीलार्थी, पैरवी सात दिवस में करें। वास्ते बहस दिनांक 25.07.2025 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश
अमरोहा

प्रार्थना पत्र 5 बी- अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रश्नगत दण्डादेश एवं अर्थदण्ड की धनराशि को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा यह कथन किया है कि नोटिस विधि विरुद्ध होने व परिवाद संधारणीय न होने के बावजूद भी आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चैक स्टॉप कराया गया था। अपीलार्थी द्वारा थाना हाजा पर प्रश्नगत चैकों की सूचना थाना हाजा पर दी थी। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया गया कि अपील प्रस्तुत करते समय धनराशि 20 प्रतिशत अर्थदण्ड धारा 148, 139 N.I.Act जमा करने का प्रावधान मैनडेटरी नहीं है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में इस विधिक प्रावधान को भाषान्तरित किया है तथा स्पष्टीकृत कर एडजुडिकेशन किया कि नोटिस के आधार पर निर्णित किया गया कि परिवाद अविधिक है। इस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जम्बू भंडारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं अन्य 2023 लीगल इगल (एस.सी.) 906** में यह अवधारित किया गया है कि:-

"6. However, in a case whee the Appellate Court is satisfied that the condition of deposit of 20% will be unjust or imposing such a condition wil amount to deprivation of the right of appeal, exception can be made for the reasons specifically recorded."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्टे प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु उठाये गये हैं, वे मामले के गुण दोष के संबंध में है तथा कोई ऐसा बिन्दु नहीं उठाया गया है जिसके आधार पर लगाये गये जुर्माने का बीस प्रतिशत जमा करना अपीलार्थी के लिए अन्यायपूर्ण या उसको अपील के अधिकार से वंचित करना जैसा होगा। तदनुसार अपीलार्थी उक्त विधि व्यवस्था का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम में एक वर्ष के साधारण कारावास व अंकन 38,00,000/- (अड़तीस लाख) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपील ग्राह्य की जा चुकी है। अतः धारा-148 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान को देखते हुए अपीलार्थी/ अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड में अधिरोपित धनराशि की बीस प्रतिशत (20%) धनराशि अर्थात 7,60,000/- रुपये पन्द्रह दिन के अन्दर न्यायालय में जमा करने पर आक्षेपित दण्डादेश का क्रियान्वयन अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगा।

सत्र न्यायाधीश
अमरोहा

प्रार्थना पत्र 7 बी- अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उसे जमानत पर रिहा करने हेतु दिया गया और कहा गया कि उसे अपील में सफल होने की पूरी आशा है। वह पूर्व में जमानत पर था, उसने जमानत का दुरुपयोग नहीं

किया है। अतः उसे अपील के दौरान जमानत पर रिहा किया जाये।

सुना एवं आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला परिवाद पर आधारित है और धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत चैक अनावृत होने पर दायर किया गया है। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि वह पूर्व में जमानत पर था। उसने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। उसे अपील में सफल होने की आशा है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त सनराईज पैकर्स द्वारा प्रोपराईटर वकार उल्ला द्वारा अंकन बीस-बीस हजार रुपये के दो जमानती एवं इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर उसे अपील के दौरान जमानत पर रिहा किया जाये।

सत्र न्यायाधीश
अमरोहा"

11. A bare look of the order dated 26.06.2025 would reveal that the same is not as per the mandate of **Jamboo Bhandari (supra)**, wherein following was observed:-

"8. The submission of the learned counsel appearing for the original complainant is that neither before the Sessions Court nor before the High Court, there was a plea made by the appellants that an exception may be made in these cases and the requirement of deposit or minimum 20% of the amount be dispensed with. He submits that if such a prayer was not made by the appellants, there were no reasons for the Courts to consider the said plea.

9. We disagree with the above submission. When an accused applies under Section 389 of the Cr.P.C. for suspension of sentence, he normally applies for grant of relief of suspension of sentence without any condition. Therefore, when a blanket order is sought by the appellants, the Court has to consider whether the case falls in exception or not.

10. In these cases, both the Sessions Courts and the High Court have proceeded on the erroneous premise that deposit of minimum 20% amount is an absolute rule which does not accommodate any exception."

12. In the opinion of the Court, the Court was under obligation to consider the fact whether the case of the applicant falls under exceptional category or not. Since the same has not been considered then the order cannot be set aside. Accordingly, the application is being decided in the following terms: -

(a) The order dated 26.06.2025 passed by the Court of Sessions Judge, Amroha in Criminal Appeal No.8 of 2025 in so far as it directs for deposit of 20% of the total amount of Rs.38,00,000/- is set aside.

(b) The matter has been remitted back to the court below to pass fresh order.

(c) Since the applicant has made the statement that the applicant shall deposit 10% of the said amount being Rs.3,80,000/-, thus the same will be deposited by 17.10.2025.

(d) The amount which will be deposited shall be adjusted post passing of the fresh order after remand.

13. In case the said amount as directed is not deposited, the consequences shall follow.

14. With the aforesaid observations, the application stands **disposed of**.

September 26, 2025

N.S.Rathour

(Vikas Budhwar,J.)